

सीआईएमपी : बिहार में सीएसआर की नई राह तलाशने के लिए जुटे विशेषज्ञ

पटना, कार्यालय संवाददाता। चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान पटना (सीआईएमपी) के सीएसआर (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉसिबिलिटी) एवं ईएसजी (पर्यावरण, सामाजिक और शासन) अध्ययन केंद्र ने यूनिसेफ और हैदराबाद विवि के सहयोग से सामाजिक उत्तरदायित्व पर बुधवार को पांचवां अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया।

इसमें नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों, कॉर्पोरेट जगत से जुड़े लोगों बिहार में सीएसआर की नई राह तलाशने को लेकर विभिन्न नीतियों और तरीके पर चर्चा की। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर राणा सिंह ने कहा कि सीएसआर को केवल चेकबुक पर परोपकार से आगे बढ़ परिणाम केन्द्रित हस्तक्षेप करना होगा। एक्सिस बैंक के डॉ. इंद्रनील डे ने कहा कि सीएसआर सार्वजनिक कल्याण का



सीआईएमपी की ओर से बुधवार को आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में अतिथि।

महत्वपूर्ण जरिया है और इसमें पारदर्शिता व स्वतंत्र मूल्यांकन जरूरी है। यूनिसेफ की प्रतिनिधि मार्गरेट ग्वाडा ने बिहार को बच्चों के लिए नवाचार का मॉडल राज्य बनाने की बात कही। डॉ. हिशमी जमील हुसैन ने बुनियादी अधिकारों को सुनिश्चित करने में सीएसआर की भूमिका पर बल दिया। नाबार्ड के लक्ष्मण कुमार ने सीएसआर आवंटन की

असमानता को सुधारने की आवश्यकता पर बल दिया। नीति विशेषज्ञ मैथ्यू चेरीयन ने बताया कि बिहार को राष्ट्रीय सीएसआर निधि का मात्र 1% ही मिलता है। डॉ. भास्कर चटर्जी ने कहा कि अभी 28 हजार कंपनियां 35 हजार करोड़ योगदान करती हैं, जो 2035 तक एक लाख करोड़ तक पहुंच सकता है। 15 से अधिक शोध पत्रों की प्रस्तुति भी हुई।

पारदर्शिता और निगरानी पर हो जोर

जागरण संवाददाता, पटना: चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट पटना में बुधवार को सीआइएमपी सेंटर फार सीएसआर एंड ईएसजी स्टडीज फाउंडेशन के अंतर्गत कारपोरेट सोशल रिस्पॉसिबिलिटी 2025 पर 5वां अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। यूनिसेफ और स्कूल आफ मैनेजमेंट स्टडीज हैदराबाद विश्वविद्यालय के सहयोग से आयोजित सम्मेलन में नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों, कारपोरेट नेताओं, विकास क्षेत्र के विशेषज्ञों और छात्रों ने भाग लिया, जहां बिहार में सामाजिक रूप से जिम्मेदार, प्रभावी और परिणाम-आधारित सीएसआर के उभरते मार्गों पर विचार-विमर्श किया गया।

सीआइएमपी के निदेशक प्रो. राणा सिंह ने कहा कि सीएसआर को अब चेकबुक पर आधारित परोपकार से आगे बढ़कर साक्ष्य-आधारित, परिणाम-केंद्रित हस्तक्षेपों में बदलना होगा, जो बिहार की विकास प्राथमिकताओं से जुड़ते हों। एक्सिस बैंक चेयर प्रोफेसर डा. इंद्रनील डे ने सीएसआर को एक ऐसे द्वितीय-श्रेष्ठ तंत्र के रूप में प्रस्तुत किया, जिसके माध्यम से निजी कंपनियां उन क्षेत्रों में सार्वजनिक कल्याण में योगदान दे सकती हैं, जहां सरकारी क्षमता सीमित है।

● सीआइएमपी में कारपोरेट सोशल रिस्पॉसिबिलिटी 2025 पर 5वां अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित

● प्रभावी और परिणाम-आधारित सीएसआर के उभरते मार्गों पर किया गया विचार-विमर्श



चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट में कारपोरेट सोशल रिस्पॉसिबिलिटी 2025 पर आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन करते शिक्षक व अतिथि ● सौ. संस्थान

उन्होंने सीएसआर को कारपोरेट लाभप्रदता और नागरिक कल्याण के बीच एक सेतु बताया, जो स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा, आजीविका और पर्यावरणीय स्थिरता जैसे क्षेत्रों में संसाधनों को निर्देशित करता है। उन्होंने पारदर्शिता, निगरानी और तृतीय-पक्ष मूल्यांकन की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि सीएसआर की विश्वसनीयता बनी रहे। यूनिसेफ की प्रतिनिधि मार्गरेट ग्वाडा ने बिहार के बेहतर होते शासन-परिदृश्य की सराहना की और सरकार, कारपोरेट क्षेत्र और

सिविल सोसायटी के बीच गहन सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने यूनिसेफ की स्वच्छता और समुदाय-आधारित पहलों का उल्लेख किया तथा बिहार को बाल-केंद्रित सीएसआर नवाचार का माडल राज्य बनाने का आह्वान किया। डा. हिशमी जमील हुसैन ने स्वच्छ पानी, गरिमा, स्वास्थ्य और पोषण जैसे बुनियादी अधिकारों को सुनिश्चित करने में सीएसआर की भूमिका पर जोर दिया एवं बहु-हितधारक साझेदारियों के महत्व को रेखांकित किया।

बिहार में देश की पहली राज्य सीएसआर नीति पर मंथन

राज्य सीएसआर नीति कॉरपोरेट जगत को स्पष्ट दिशा देती है : भास्कर चटर्जी

पटना/संवाददाता। बिहार की नव अधिसूचित राज्य कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) नीति को प्रभावी अमल तक पहुंचाने की दिशा में यूनीसेफ और चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पटना (सीआईएमपी) ने बड़ी पहल की। पटना में आयोजित 5वें अंतरराष्ट्रीय सीएसआर सम्मेलन के दौरान दोनों संस्थानों ने उच्च-स्तरीय गोलमेज बैठक आयोजित की, जिसमें बिहार राज्य सीएसआर नीति 2025 के ढांचे को मजबूत करने और इसके जमीनी क्रियान्वयन पर विस्तार से मंथन हुआ। गौरतलब है कि बिहार देश का पहला राज्य है, जिसने अपनी अलग राज्य सीएसआर नीति तैयार कर अधिसूचित की है। भारत में सीएसआर के जनक कहे जानेवाले और आईआईसीए के पूर्व महानिदेशक भास्कर चटर्जी ने बैठक में कहा कि यह नीति कॉरपोरेट जगत को स्पष्ट दिशा देती है, लेकिन बिहार में निवेश आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन प्रावधानों पर गंभीरता से विचार जरूरी है। यूनीसेफ बिहार की प्रमुख मागरिट ग्वाडा ने कहा कि सीएसआर साझेदारियां जल, स्वच्छता व स्वास्थ्य, पोषण और बच्चों से जुड़े कार्यक्रमों में बदलाव की रफ्तार तेज कर सकती हैं। वहीं सीआईएमपी के निदेशक प्रो. (डॉ.) राणा सिंह ने कहा कि सामाजिक निवेश तब असरदार होगा, जब वह अल्पकालिक गतिविधियों से आगे बढ़कर दीर्घकालिक और टिकाऊ बदलाव का आधार बने। उद्घाटन सत्र में वर्चुअल रूप से शामिल अरामको,



सऊदी अरब के हिशमी जमील हुसैन ने बिहार को सामाजिक निवेश के लिए हाई रिटर्न जियोग्राफी बताया। वहीं हेल्पएज इंडिया के पूर्व सीईओ मैथ्यू चेरियन ने सीएसआर फंड का संतुलन ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों की ओर बढ़ाने पर जोर दिया। नाबार्ड के डीजीएम लक्ष्मण कुमार ने आजीविका, कौशल विकास और ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रमों में बेहतर तालमेल की आवश्यकता रेखांकित की। इसके बाद हुई गोलमेज चर्चा बिहार सीएसआर पोर्टल के विकास और नीति के क्रियान्वयन के व्यावहारिक पहलुओं पर फोकस रहा। यूनीसेफ इंडिया की पार्टनरशिप स्पेशलिस्ट रमोना बक्शी के संचालन में हुई इस चर्चा में पैलेडियम इंडिया, ज्यूबिलेंट इंग्रेविया, अपोलो मेडिस्कल्स, टेरी, आईसीआईसीआई फाउंडेशन, अरामको, नाबार्ड फाउंडेशन और वाबटेक के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

सीआईएमपी: सीएसआर नीति पर विस्तार से मंथन

पटना|बिहार की नव अधिसूचित राज्य कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नीति को प्रभावी अमल तक पहुंचाने की दिशा में यूनिसेफ और चाणक्य इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक लीडरशिप ने बड़ी पहल की। पटना में आयोजित 5वें अंतरराष्ट्रीय सीएसआर सम्मेलन के दौरान दोनों संस्थानों ने उच्च-स्तरीय गोलमेज बैठक आयोजित की, जिसमें बिहार राज्य सीएसआर नीति 2025 के ढांचे को मजबूत करने और इसके जमीनी क्रियान्वयन पर विस्तार से मंथन हुआ। गौरतलब है कि बिहार देश का पहला राज्य है, जिसने अपनी अलग राज्य सीएसआर नीति तैयार कर अधिसूचित की है। भारत में सीएसआर के जनक कहे जाने वाले और आईआईसीए के पूर्व महानिदेशक भास्कर चटर्जी ने बैठक में कहा कि यह नीति कॉर्पोरेट जगत को स्पष्ट दिशा देती है, लेकिन बिहार में निवेश आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन पर गंभीरता से विचार जरूरी है।

सीआईएमपी में आयोजित हुआ अंतरराष्ट्रीय सीएसआर सम्मेलन, बिहार को बताया संभावनाओं का केंद्र

पटना। चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पटना (ष्टुट्टुस्क) ने यूनिसेफ और हैदराबाद विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के सहयोग से 'कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी 2025' पर पाँचवाँ अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। इस कार्यक्रम में नीति-निर्माताओं, शिक्षाविदों, कॉर्पोरेट नेताओं और छात्रों ने बिहार में सामाजिक रूप से जिम्मेदार एवं परिणाम-आधारित सीएसआर के नए आयामों पर विचार-विमर्श किया। निदेशक प्रो. राणा सिंह ने बताया कि भारत में सीएसआर व्यय 2014 में 20 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर 2020 में लगभग दो लाख करोड़ रुपये हो गया है। अब इसे केवल परोपकार नहीं बल्कि विकास का साक्ष्य-आधारित साधन बनाना होगा। डॉ. इंद्रनील डे ने कहा कि सीएसआर कंपनियों को सार्वजनिक कल्याण से जोड़ने का माध्यम है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में काम कर सकता है। यूनिसेफ की प्रतिनिधि मागरिट ग्वाडा ने बिहार की प्रगति की सराहना करते हुए बाल-केंद्रित सीएसआर नवाचार को प्रोत्साहित करने की बात कही। वहीं नाबार्ड के लक्ष्मण कुमार ने बताया कि संस्था ने 43 भागीदारों के साथ 300 से अधिक परियोजनाओं में 2,000 करोड़ रुपये का निवेश किया है। कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने बिहार को उभरते हुए सीएसआर केंद्र के रूप में रेखांकित किया।